WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Export credit applications received by Exim Bank

*84. SHRIGHUFRAN AZAM: WiH the MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Exim Bank, New Delhi has received a number of applications from leather exporters for facilitating post-package export credit;

(b) whether it is a fact that the applications have neither been properly looked into nor has there been appropriate action taken to help the exporters; and

(c) if so, the facts and reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKAR MURTHY): (a) The Hon'ble Members question presumably relates to export packing credit or post-shipment credit. The Export Import Bank of India has reported that their New Delhi Office has no pending application from leather exporters for export packing credit or post-shipment credit.

(b) and (c) Do not arise.

देश पर वित्तीय बोझ में वृद्धि होना

*85. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 नवम्बर, 1994 के दैनिक ऑब्जरवर में "इंडियाज़ डैट लाइबिलिटी टु टच 5,33,053 करोड़–स्टडी–" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मार्च, 1995 के अन्त तक सरकार पर घरेलू ऋण का बोझ 5,33,053 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकारी अनुमान क्या हैं; और

(घ) देश पर वित्तीय बोझ में अप्रत्याशित और अनावश्यक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में उल्लिखित 5,33,053 करोड़ रुपए का आंकड़ा वही हैं जो संसद् में दिनांक 28–2–1994 को प्रस्तुत किए गए प्राप्ति बजट, 1994–95 में उल्लिखित हैं परन्तु यह मार्च, 1995 के अंत तक केन्द्र सरकार की कुल अनुमानित देनदारियों (घरेलू और विदेशी) से संबंधित है । तथापि वर्ष 1994–95 के बजट अनुमान में घरेलू ऋण बोझ का अनुमान 4,83,245 करोड़ रुपए लगाया गया है ।

(घ) सरकार राजस्व और अन्य गैर-ऋण प्राप्तियों में कमी की सीमा तक संसद् द्वारा अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए उधार लेती रही है। व्यय विभिन्न शीर्षों विशेषकर रक्षा, आर्थिक सहायता, आंतरिक सुरक्षा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान, आयोजना व्यय और सबसे अधिक पिछले ऋणों पर ब्याज संदाय के अंतर्गत बढ़ता रहा है । सरकार चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त उधारों को यह सुनिश्चित करते हुए 54,915 करोड़ रुपए के बजटीय स्तर तक सीमित रखने का प्रयास करेगी कि व्यय बजट अनुमान से अधिक न होने पाए और प्राप्तियों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए ।